साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 23 | प्रति सोमवार इंदौर, 8 जनवरी से 14 जनवरी 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

चीन प्रेमी मोदी ने मोटे कमीशन पर

देश के किये उद्योग धंधे बर्बाद, सीमाओं पर घुसपैठ की पूरी छूट

आखिर चीन के राजनयिक दल ने आरएसएस नागपुर मुख्यालय पहुंच क्या गुटर गूं की, बताओ देश को

भारत की सत्ता छल बल दल से हथियाने के बाद मोदी का चीन प्रेम और गहरा हो गया। चीन के गहने प्रेम की वजह मोदी को अमेरिका ने मुख्यमंत्री रहते गोधरा कांड करवाने व अन्य प्रकार के अनेकों सार्वजनिक अपराध करने के कारण वीजा देना से मना कर दिया था। जिससे मोदी को गहरा धक्का लगा और वह चीन के प्रति धन लेकर देश को बर्बाद करने अधिक उदार हो गया जिसके परिणाम सामने है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उसने चार बार चीन की यात्राएं की और चीन के बड़े उद्योगों से मोटा पैसा लेकर पूरे गुजरात में चीन ने बड़े-बड़े एकाधिकारी पारंपरिक उद्योगों व्यवसायों को नष्ट करने बड़ी-बड़ी चीनी कंपनियों के हर क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग धंधे कंपनियां रोजगार खड़े कर दिए। इसमें औषधीयां, टाइल्स, वस्त्र उत्पादन, औद्योगिक वाहन घरेलू उद्योग मशीन, रसायन, वैद्युतकीय एवं विद्युताग्र, मशीन तार उपकरण हीरा रत्नों की कटिंग आदि जिन में भारत का एकाधिकार व दबदबा था। चीनी कंपनियों को सौंप कर उनको उन क्षेत्रों में पूरी दुनिया में अपना व्यवसाय करने के लिए कुशल श्रमिक मशीन साधन उपलब्ध करवा कर गुजरात के उद्योग धंधों को बर्बाद किया। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने चीनी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन खाकर देश में सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी के नाम पर लगभग 2 करोड़ छोटे उद्योगों धंधों दुकानों व्यवसायों को नष्ट कर दिया। इसका सीधा फायदा चीन को हुआ और आज वह भारत से आयात की अपेक्षा चौगुने से ज्यादा भारत को निर्यात कर उसने पूरी दुनिया के चीनी कबाड़ माल जिसमे खिलौने से लेकर रडार इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन वस्त्र तैयार वस्त्र रसायन औषधीय का कच्चा माल भारी मशीन ऑटोमोबाइल कारों से लेकर स्कूटर दोपहिया वाहनों के इंजन तक त्योहारों पर खर्च होने वाली राखी भगवानों की मूर्तियां दिए पटाखे रंग गुलाल पिचकारी तक को भारत में बेचने और हमें उत्पादक की जगह उपभोक्ता देश बना दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए उसने तीन बार चीन की यात्राएं की और कोरोना के समय पर उसने दो किस्तों में लगभग डेढ़ सौ अरब डॉलर विभिन्न माध्यमों से लेकर चीन को न केवल देश के अंदर वरन देश की सीमाओं पर भी हर तरह का अतिक्रमण कब्जा करने की खुली छूट दे दी।

(शेष पेज 6 पर)

भारत की जीडीपी 7.3 का अनुमान बकवास झूठे आंकड़ों की बाजीगरी

सारी संस्थाओं को 2014 के बाद नकारा बना लूट नाकामियों बर्बादी को छुपाने का षड्यंत्र

सारी संस्थाएं रिजर्व बैंक, भारत व राज्यों के सांख्यिकी विभाग, भारत का लेखा नियंत्रक, स्टेट बैंक बीमा कंपनियां आदि दवाब में फर्जी आंकड़े दिखा प्रशंसा कर बच रहीं

भारत में मोदी के सत्ता में आने के बाद उसके मित्रों के इशारे पर सारे वित्तीय संस्थानों रिजर्व बैंक से लेकर सभी बैंकों को लूटने का षड़यंत्र तो आपने देखा जिसकी 10% खबरें ही बाहर आ पाईं। फिर उसने जिसके बैंकों के बैंक को वित्तीय संस्थाओं का संस्थान रिजर्व बैंक से उसके आरक्षित निधि का भी दवाब डलवा कर लगभग 50 लाख करोड रुपए निकाल लिया और सुशिक्षित समझदार देश कार्य करने ब्रिटिश संस्थाओं को संभालने के लिए सक्षम और होशियार व्यक्ति राजन को बाहर निकाल दिया बाद में अंबानी का जीजा उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का राज्यपाल नियुक्त किया। जब उसने भी सारे छल कपट और लूट में साथ देने से मना कर दिया। तो फिर इतिहास के विद्यार्थी घोर भ्रष्ट जालसाज अधिकारी शशिकांत दास को रिजर्व बैंक का राज्यपाल बना दिया। तो यह स्वाभाविक है। आका के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करेगा। तो जीडीपी 7.2 के अनुमान के बारे में समझा जा सकता है कि वह केवल मोदी की सत्ता व कार्यकाल की प्रशंसा में कसीदे ही पढ़, जारी कर सकता है। जबकि हमारा देश भुखमरी में 111 नंबर पर बेरोजगारी में 123 नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 129वें नंबर पर है।

इन देशों में है सबसे ज्यादा बेरोजगारी, टॉप-5 में भारत भी शामिल

दुनिया के कई देश भारी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि भारत सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के हिसाब से दुनिया के चोटी के देशों में शामिल है... बेरोजगारी की समस्या कई देशों के लिए अभी गंभीर हो चुकी है. भारत में तो दशकों से बेरोजगारी गंभीर चुनावी मुद्दा बनता आया है और इसके कारण अनेकों आंदोलन देखने को मिले हैं. अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के हिसाब से बात करें तो भारत भी दुनिया के चोटी के देशों में शामिल है.

इतनी है भारत में बेरोजगारी

सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 में भारत में बेरोजगारी की दर लगातार दूसरे महीने बढ़कर 7.8 फीसदी हो गई थी. सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार, मार्च महीने के दौरान भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.51 फीसदी रही थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 7.47 फीसदी थी. इस तरह देखें तो पता चलता है कि अभी अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति काफी गंभीर है. (शेष पेज 6 पर)

सातवीं बार स्वच्छता का पुरस्कार खरीदा

80% शहर की सड़कें खुदी हुई धूल उड़ाती ऊबड़ खाबड़ गंदगी युक्त

सच जानने पिछले वर्ष के इंदौर के दैनिक पत्रों के हर दिन छपने वाले समाचार बयां करते हैं

देश के सर्वोच्च पद को छल कपट ईवीएम की जालसाजियों से हथियाने वाले आपराधिक मानसिकता के मोदी और शाह ने अच्छे खासे देश को छल कपट और बर्बादी की राह पर धकेल दिया। अब शासन की योजनाओं का वित्तीय लाभ लेने, अधिक धन की मांग करने के लिए सारे छोटे- छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक अपनी मोटी कमाई के लिए शासकीय स्तर पर झूठे फर्जी आंकड़ों वीडियो का खेल पूरे देश में चलाया जा रहा है इंदौर उससे अछूता नहीं। यहां के सभी पिछले 40 वर्षों से पदस्थ होने वाले जिलाधीशों, पटवारी, राजस्व, निरीक्षक, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, अधिकारी कॉलोनी सेल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का संयुक्त संचालक जिला नियोजक गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त से लेकर करण पालन यंत्रियों सहायक यंत्रियों उपयंत्रियों तक, वही हाल नगर निगम पालिकाओं में बैठे सहायक आयुक्त, उपायुक्त, सिटी से नगर नियोजक इंजीनियर जैसे इंदौर में वर्षों से कुंडली मारे अनूप गोयल बैठा हुआ है। वही हाल सिटी इंजीनियर कर पालन यंत्री सुनील गुप्ता भी कुंडली मारे जमा हुआ है से लेकर निरीक्षक गली मोहल्ले के दरोगा तक शुभ माफियाओं कानूनी माफियाओं के संरक्षक कमीशन खोरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

कानून धुर्तों के बनाए शब्दों के मायाजाल जो अपनों के पोषण निरीहों के शोषण के हथियार

सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में कानूनों की, और उसकी परिभाषा की मेरे पास में 3 साल के कानून की एलएलबी की डिग्री को मैंने नौकरी के चक्कर में 7 साल में पास किया है। पांच बार बीकॉम एलएलबी डिप्लोमा इन लेबर लॉ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट सीए आइसीडब्लुए में 58 श्रम कानूनों की परीक्षा दी है। इसके बाद गहन अध्ययन के निष्कर्ष में निकला कि यथार्थ में कानून धूर्तों के बनाये शब्दों के मायाजाल हैं जो अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के हथियार के रूप में काम आते हैं। वर्तमान की आपराधिक मानसिकता के जाहिलों के सत्ता के सभी कानून सत्ता के मद में चूर होकर जनहितों को त्याग अपने मित्रों के पोषण और बेरोजगारी भूख गरीबी से त्रस्त 100 करोड़ गरीब बेबस जनता के शोषण, परेशान करने उनको उलझाए रखने और अपने सारे कुकर्मों को छुपाए रखने के लिए बनाये जा रहे हैं। या बनाये गये हैं। ताकि वह देश को बेंचते रहें पूंजीपतियों को नीलाम करते रहें देश के पैसे को दुबई भेज वहां से बाहर भेजें और विकास के नाम मोटे कमीशन के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर कर्जा लेकर घी पीते रहें। देश की जनता को एक तरफ कानून में उलझा, विश्व घातक संगठन व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए उनके इशारे पर सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी कोरोना की आड़ मेंऔर उसका तांडव कर 30 करोड़ को बेरोजगार बनाकर भूख से मारने, मरते हुए लोगों को वोटों के लिये जिंदा रखने रु. 1 किलो का गेहूं रु. 2 किलो का चावल खिलाकर जानवर बनाकर उनका रक्त पान करते रहे राक्षस। यह ठोको और भागो कानून उसी का हिस्सा है। आपके घर में अगर स्कूटर, मोटर साइकिल कार वगैरह कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं चलाते हैं। तो भी कोई बात नहीं। पर आपके बच्चे तो चलाते हैं। उनकी गाड़ी चलाते समय कोई भी बच्चा सारे बचाने के प्रयास करने के बाद में भी अगर अचानक उसकी गाड़ी में घुस गया और दुर्भाग्य से वह मर भी गया। आपका बच्चा नाबालिग था। या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या था। अगर नाबालिग था। तो बच्चे की सजा के साथ आपको भी सजा भुगतना ही है और जुर्माना भी भरना है। अगर बालिग लाइसेंस भी है। और सारे बचाने के प्रयास करने के बाद में भी दुर्घटना हो जाती है। फिर डरपोक अंधभक्त हिंदुओं आपका एक ही बच्चा ठोकर डाकू केस में फस गयाउसकी जिंदगी तो बर्बाद हुई हुई आपका भी घर तबाह हो गया कोई कानून नहीं उसकी कोई गलती थी या नहीं थी। का कोई मतलब नहीं उसके पास बड़ी गाड़ी थी उसी गाड़ी में कोई घुसकर भी मर गया तो भी 10 लाख रु जुर्माना माता जी बीवी के गहने बेंचो मकान बैंचों दुकान खेत गाड़ी बेंचो। और बेटा या बेटी माता-पिताबहु नाती पोते 10 साल के लिए जेल में जब बाहर निकले तो पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। मध्य प्रदेश में केंद्र के गजट नोटिफिकेशन के बावजूद भी रु. 200 के लाइसेंस के रु. 5000 लगते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव परिवहन सचिव परिवहन मंत्री को इस षड़यंत्र के आरोप मेंजेल में क्यों नहीं डाला जाता। केंद्र सरकार के बजट नोटिफिकेशन के विपरीत सभी परिवहन के शुल्क 10 गुना तक ज्यादा है। पहले ही बेरोजगारी फिर अगर नौकरी मिल भी गई याद रु. 10000 की तो बेचारा युवा लड़का लड़की अपना खर्च चलाएं यह रु. 5000 का लाइसेंस बनवाए। फिर आपकी गाड़ी गड्ढे में घुस गई एक्सीडेंट में मर गए। 90% सड़क दुर्घटनाओं में सड़कों की उचित चौड़ाई बनावट रख-रखाव मोड़ों और चोराहों कि गलत बनावट पर निगम पालिकाओं पुलिस का वसूली पूर्ण रवैया ऑन ट्रैफिक नहीं सुधरना 90% मामलों में जनता को जानबूझकर नियम तोड़ने पर विवश कर वसूली करना होता है और उससे बचने के लिए दुर्घटनाएं भी होती हैं तो भी गलती केवल वाहन चालक कीकोई मर गया इस बीच तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल तो अंधभक्तों कुछ तो अच्छा है। बेशक हमारे युवाओं विशेष रूप से धनाढ्य माता-पिता के युवाओं में ठोको भागो की आदतें बहुत ज्यादा पाई जाती है यह सच है। परंतु यह एक कड़वा सच और समझ लीजिए। कानून की एक सर्वमान्य विशेषता यह भी है कि बड़ा मानता नहीं छोटा जानता नहीं। हर बार फंसता है तो मध्यमवर्गीय। और दुनिया के 90% कानून मध्यमवर्गों पर थोपे जाते हैं। उन्हीं से भारी टैक्स वसूल किया जाता है उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती उन्हें 24 घंटे गाली बकी जाती है। उनका हर कानून की आड़ मैं सबसे ज्यादा शोषण करने के साथ उन्हें मारा डराया धमकाया जाता है। तो इस कानून में बुरा बहुत ज्यादा है। इसको भी समझिए अंडभक्ति में इतने अंधे मत हो जाइए कि आपका परिवार समाज और राष्ट्र बर्बाद हो जाए हरामखोरों। वैसे अंड भक्तों तुम्हारी औकात पानी के बहाव में बहने वाले मुर्दों से ज्यादा व सियारों की तरह हुआ-हुआ करने वालों से ज्यादा कुछ नहीं। यही अंधभक्त हमारी हजारों साल की गुलामी का कारण रही है और अब पुनः पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलामी का कारण बनने जा रही है।

80% शहर की सड़कें खुदी हुई धूल उड़ाती ऊबड़ खाबड़ गंदगी युक्त

पेज 1 का शेष

जिनका उद्देश्य छल कपट और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अपनी कुकर्मों से नजर हटाने लूटपाट जालसाजियों को वैध व उचित बताने बनाने शहर को स्वच्छता का वाटर प्लस वह अन्य पुरस्कार दिलवाये जाते रहते हैं। 80% गलियां पिछले 20 सालों में जो 5000 करोड रुपए से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से नालियां बनाने सिवर लाइन डालने के नाम पर बनी बनाई सीमेंट की सड़कों को खोदने बर्बाद करने उस पर पुनः कांक्रिटिंग करने डामर डालने सड़कें बनान के नाम पर हजम कर चुके हैं।

और जो वर्तमान शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गी कहते हैं के अनुसार को सब छोड़कर बनाया उनको यह भी बताना चाहिए पिछले 20 सालों में जब वे यहां के महापौर थे कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही थीं। तब उन्होंने नालियों की उचित व्यवस्था निर्माण क्यों नहीं किये? जो उनके महापौर बनने व हटने के बाद से लगातार 20 सालों से लगातार बनी बनाई सड़कें तोड़ फोड़ कर डाली व बनाने के नाम सेकड़ों करोड़ जनता के, विश्व बैंक के ऋण के, जेएनयूआरएम के बर्बाद कर हजारों करोड़के ठेकों में 20 से 70% तक कमीशन हजम कर बनवाने का खेल क्यों चल रहा है और उसी के कारण गली मोहल्लों की सड़के तोड़ी-फोड़ी जाती हैं फिर बनाई नहीं जाती जबकि इस प्रकार के हारतेरो पत्र में ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि सड़क तोड़ने फोड़ने के बाद वह पूर्व की तरह कंक्रीट की होने पर कंक्रीट की बनाएगा और डामर की होने पर डामर की बनाएगा परंतु भाई कभी नहीं बनता केवल थिगड़े और हल्के फुल्के डामर के बिना भारी कुटाई भराई किये डामर मिली गिट्टी बजरी की परतों के लेप लगा दिए जाते हैं।

जिससे नेहरू नगर की गली नंबर 9 पर ही सारे दिन धूल उड़ा करती है और पुनः गड्ढे हो जाते हैंजिससे चलने वालों को न केवल परेशानियां होती हैं बल्कि दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जा चुकी हैं। परंतु इससे महापौर पु मि भार्गव निगम आयुक्त हर्षिका सिंह से लेकर उपायुक्त सहायक आयुक्त निगम इंजीनियर सुनील गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबने मोटा कमीशन हजम किया होता है। अन्य कुकर में पर्दा डालने मोटा पैसा खर्च कर पुनः पुरस्कार लिया जा रहा है और नगर प्रदेश देश की जनता के साथ विश्व की जनता को भी मॉडल स्वच्छ शहर दिखाने के नाम पर भी वसूली की जाएगी 2000 रु की और रु. 2000 देने के बाद उस उड़ती हुई धूल उबड़ खाबड़ सड़कों, सड़क किनारे लगाए गए कचरो के डिब्बे जो 90% गायब हो चुके हैं। पर कागजों में उनकी मरम्मत रखरखाव पुणे खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए लगातार खर्च किए जा रहे हैं और वह पैसा सीधा कागजों से चुने हुए पार्षदों महापौर और निगम के अधिकारियों की जेब में जा रहा है। पर टीका टिप्पणी कौन और क्यों करेगा अन्यथा उनकी अगवानी करने आए अधिकारी उन्हें नए शहर में अकेला छोड़कर बदतमीजी दिखाकर भाग जाएंगे। इस बकवास का सच नगर की जनता हर दिन छपने वाले सैनिक ऑन समाचार पत्रों के माध्यम से देख समझ रही है के साथ जो हजारों शिकायतें दबाव देकर धारा धमका कर जनता के द्वारा की जाती हैं कोई या तो सुना ही नहीं जाता या कार्रवाई करने की अपेक्षा लोगों के शौचालयों स्नानागारो की की पाइप लाइनों में बोतल एट मिट्टी गिट्टी बुरे फंसा कर सफाई के नाम पर हजारों रुपए भी मांगे जाएंगे परेशान भी किया जाएगा और उनके द्वारा दर्ज मुख्यमंत्री ऑनलाइन की शिकायत को बंद करवा दिया जाएगा तो सफाई का पुरस्कार देने से पहले समाचार पत्रों की दैनिक सड़कों के बारे में शहर की साफ सफाई खुदी हुई सड़कों के बारे में पढ़ी जा सकती हैं दूसरी तरफ जब आपके उपग्रह इतने सटीक जानकारी देते हैं तो दिल्ली स्थित कार्यालय हमको इंदौर की मुख्य कुछ मार्गों की सड़क छोड़ दी जाए तो आंतरिक सड़कों की जानकारी उपग्रहों के माध्यम से बहते हुए सिविल लाइन का पानी सड़कों पर कीचड़ के लोगों को निकालने में परेशानियां देखकर पुरस्कार दिया जाना चाहिए थे और यह कड़वा सच इंदौर के प्रेस कांप्लेक्स के पीछे बसी हुई मालवीय नगर की सड़कों पर भी देखा जा सकता है वैसे तो पूरे नेहरू नगर के साथ जूना रिसाला जिंसी एमजी रोड से जुड़ी हुई सारी गलियां कॉलोनीयों की सारी गलियों में पहले से पड़े हुए पाइपलाइन खुदी हुई सड़कें देखकर भी की जा सकती थी। परंतु अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए धन देने के लिए इस प्रकार के पुरस्कार देना भी केंद्र सरकार की मजबूरी है।

इंदौर को सातवीं बार स्वच्छता के पुरस्कार के नाम पर देखा जिलाधीश निगमायुक्त के साथ महापौर पार्षदों निगम के सारे अधिकारियों कर्मचारियों के सारे भ्रष्टाचारी जालसाजियों लूट डकैती की कुकर मुंह से ध्यान हटाने के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी के इसारे पर नाच कर पुराने बाजारों को तोड़ने फोड़ने सड़के चौड़ी करने के नाम उनका व्यवसाय बर्बाद कर, छोटे बाजारों में ठेलों पगमार्गों पर व्यवसाय करने वालों को साफ करने से शॉपिंग मॉल चलाने उनके व्यवसाय बढ़ाने से मिलने वाला कमिशन मैं सबको हिस्सा मिलता है। दूसरी तरफ जितने भी भाजपा कांग्रेस के नेता, अधिकांश बड़े समाचार पत्र वाले और टीवी चैनल वाले सब बड़े भू कॉलोनी माफिया हैं। जिन्होंने गृह निर्माण मंडल, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम की नजूल की, नदी नालों के बहाव क्षेत्र, कृषि भूमि आदि पर अवैध रूप से कब्जे कर कालोनियों बहू मंजिला भवन खड़े किये हैं। निगम व जिले के कलेक्टर कमिश्नर से लेकर भवन अनुज्ञा अधिकारी, नगर यंत्री से लेकर दरोगा तक, टीएंडसीपी, आइडीए मप्र गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों तक सबको पैसा पहुंचाया है।

तो सीधी सी बात है प्रदेश के इंदौर को सातवीं बार स्वच्छता का अवार्ड मिलने से उनकी जमीनों, कालोनियों फ्लेटस की कीमत बढ़ाने के साथ उनके फ्लैट मकान की कीमत बढ़ जाने से बिकने पर पंजीयन विभाग को, निगम को आपको आय मिलना स्वाभाविक है। इसलिये स्वच्छता के सातवें बार पुरस्कार के मिलने से शहर की इज्जत बढ़ने से उनकी कीमतों की बढ़ोत्तरी का फायदा अधिकारियो भू कालोनी बिल्डिंग माफियाओं नेताओं को पिछले 7-8 साल से लगातार कई गुना मिला।

मप्र जल लूट संसाधन विभाग

नियमों के विपरीत जनधन से खरीदे गद्दे, तकिये, पलंग

क्या मंत्रीजी को भेंट किये, घर रखे, देवास में विभाग का विश्राम गृह नहीं

देश और प्रदेश का जल संसाधन विभाग अपने भ्रष्टाचार के लिए विख्यात रहा है। वर्तमान में भी चारों तरफ लगभग पूरे प्रदेश में विभाग के साथ नर्मदा घाटी में भी एक लाख करोड रुपए से ज्यादा की जल उद् वहन परियोजनाएं चल रही हैं। जबकि 70-80 के दशक में जल संसाधन विभाग में जल उद्‌वहन परियोजनाओं को भारी घाटे का सौदा खर्चीला और रखरखाव में परेशानी पैदा करने के साथ बिजली के खर्च के कारण बंद कर दिया गया था। वर्तमान में प्रदेश में और नर्मदा घाटी में अधिकांश परियोजनाएं सूक्ष्म सिंचाई के नाम पर उद् वहन परियोजनाएं ही बनाई जा रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा खर्च पानी को जल भंडारण जो कि बांध या बहती नहरों के स्रोत से हजारों किलोवाट की मोटर पंप हाउस व पाइप लाइनों से उठाकर ऊंचे स्थान के जल संग्रहण केंद्र पर पहुंचा कर खेतों में वितरण हेतु पाइप लाइनों से पहुंचने की अत्यधिक खर्चीली जिसमें मोटा कमीशन खरीदी में और बचाने के कार्यों में मिलता है करवाई जा रही है बेशक देवास में ऐसी एक बड़ी हाट पिपलिया परियोजना जिसमें एलएनटी को पहले 3800 करोड़ का जो बढ़ाकर अब 6000 करोड़ के लगभग हो गया है। बनाई जा रही है जबकि वहां जरूर का मत 30% स्टाफ संभाग का है और ऐसी बड़ी परियोजना के लिए मुख्य अभियंता दो अधीक्षण यंत्री और लगभग 3 से 4 कार्यपालन यंत्री लगभग 10 से ज्यादा सहायक यंत्री और 40 से 50 उपयंत्रियों की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार यह आवश्यक स्टाफ प्रस्तावित है। पर पिछले 2 साल से जो संभाग स्तर का स्टाफ जिसमें ऐतिहासिक घोर भ्रष्ट, जालसाज कार्यपालन यंत्री जादौन सहायक चा, गुंजन सक्सेना, यादव व उपयंत्रियों जिन्होंने मोटा पैसा पूर्व में भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया वही दिया। उन्हीं को पदस्थ किया गया है। जिनमें पूर्व में दतुनी बांध व उसकी 35 किमी से ज्यादा लंबी नहरों परपड़ी बांध, चंद्र केसर की 41 किमी की लंबी नहरों की मरम्मत कार्यों में स्तरहीन औपचारिकता पूर्ण 30 से 40% का काम करवा कर सारा पैसा हजम कर लिया गया है। जिसके समाचार अनेकों समाचार पत्र में छपने के बाद में भी क्योंकि पूर्व का भ्रष्ट जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पुनः इसी विभाग का मंत्री बना दिया गया है। उसने ही मोटा पैसा लेकर इस भ्रष्ट गिरोह को वहां पदस्थ किया है। महीने की किस्त लाखों में सभी से आती रहे।

यही कारण है कि यह हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा अपने लिफाफा नहीं लगाया था। हमने आपके शुल्क का पत्र अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया था। आपने नहीं देखा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।

तो जैसे यदि यह उसूल्की के पत्र का लिफाफा आवेदक को डाक से भेज देते तो उनकी जेब से सरकार उसका पैसा काट लेती है। परंतु इसकी आड़ में जो खेल खेला जाता है वह है, कि जब तक सामने वाला अपील न लगाये। तब तक उसके पत्र का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है और सामने वाला अपील लगा दे। तो मनमाना आवेदन की तारीख से 20-25 दिन बाद का पुरानी तारीख का जवाब लिखकर बोर्ड पर टांग दो। और अपील की सुनवाई होने पर कह दो आवेदक ने समय पर पैसे जमा नहीं किये। अगर आवेदक मनमानी हजार रुपए की राशि जमा कर दे तो उसे दस्तावेज देने को तैयार है और फिर भी आप भी लगाकर पैसे जमा कर दे तो जानकारी उसने नहीं मांगी है उतने हजार रुपए की आधी रु. 2 प्रति पन्ने के हिसाब फोटो कॉपी करवा कर उसको गट्ठा पकड़ा दो जब खोले पढ़े समझे तो मालूम पड़े की जो उसने मांगा था उसको मिला ही नहीं। जबकि चाहे गई जानकारी का 90% धारा चार केंद्र का 25 बिंदुओं की जानकारी में सौम्या हर विभाग को हर जिला अधिकारी को अपनी साइट पर लोड कर देना चाहिए था जो 18 साल के बाद में भी आज तक लोड नहीं हुआ। जो कुछ जानकारी उसमें अपलोड की गई है वह इस तरीके से लोड की जाती है ताकि उनके सारे पाप उसमें छुपी रहे। कुछ सामने ना आए जबकि यथार्थ यह है की हर जिले संभाग में कौन-कौन से काम चल रहे हैं कितना धन आया था कितना धन किस मद में खर्च कर दिया गया। कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी उनका जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यताएं स्कूल शिक्षा का प्रमाण पत्र अंक सूचियां तक जिसके आधार पर नौकरी कर रहे हैं। सब विभागीय साइट पर हर महीने आद्यतन किये जाने चाहिए। जबकि अधिकांश विवाह की साइट है मीना सालों तक अपलोड नहीं की जाती। यहां तक की मुख्य अभियंता कार्यालय उज्जैन खुले हुए 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है परंतु साइट पर अभी तक जानकारी अद्यतन नहीं की गई।

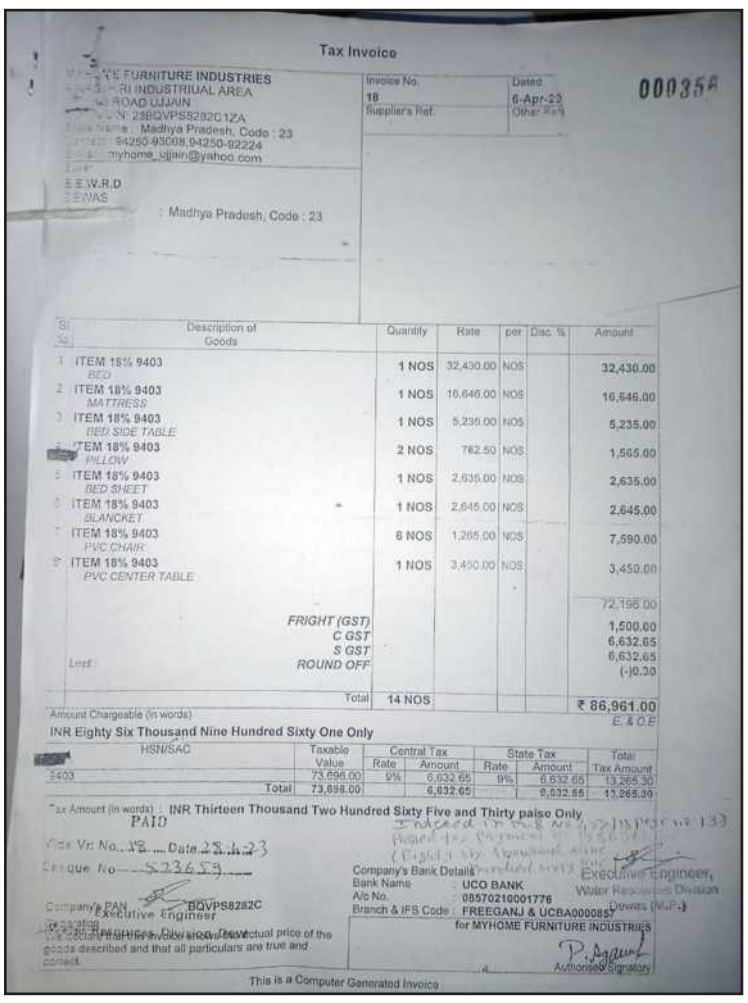

जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कारभार संभाले महीना भर भी नहीं हुआ पर जैसे शिवराज सिंह चौहान सत्ता से हटते ही भाजपा का और प्रदेश का दुश्मन बन गया तत्काल उसके सारे फोटो डीटेल्स हटाकर चारों तरफ हर विभाग की साइट पर जाहिल मोदी और खानदानी शराब, भू कॉलोनी ईंट भट्टा खनन परिवहन माफिया के मुख्यमंत्री बनते ही साथ चारों तरफ हर सरकारी साइट पर बदलाव कर फोटो लगा दिया गया है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो उस संभाग में तो हजारों करोड़ के काम आवश्यक है पर विवाह की कैश बुक भी घर पर ठेके पर लिखवाई जाती है। वर्तमान में पदस्थ स्टाफ जो वरिष्ठ लेखा लिपिक इतना भी सक्षम नहीं कि वह रोकड़ बही भी ढंग से लिख सके। यही कारण है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए माय होम फर्नीचर इंडस्ट्रीज देवास रोड इंडस्ट्रियल एरिया उज्जैन से इनवॉइस नंबर 18 तारीख 6 अप्रैल 23 से एक पलंग (बेड) रु. 32430/- एक गद्दा रु. 16646/- दो तकिए रुपए 1565 /- एक चादर रुपए 2635 एक कंबल रुपए 2645 पीवीसी सेंट्रल टेबल 3450 बेडसाइड टेबल 5235 पीवीसी 6 चेयर रु 7590 खरीद नियमों के विपरीत की गई फर्नीचर खरीदने और उसमें भी विशेष तौर से पलंग गद्दा कंबल चादर किसके लिए क्यों खरीदा गया। जबकि उसकी पात्रता ही नहीं थी। इसका वाउचर क्रमांक 18 दिनांक 28 चार 23 से चेक क्रमांक 523659 से किया गया। इसके कार्य आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई जबकि भी लगातार साल भर से ठहराव पंजी की प्रतियां द सीडी मांग रहा हूं।

फिर प्रदेश की सट्टा का मुख्यमंत्री बदलाव होगा सबसे ज्यादा घोर भ्रष्ट जालसाज होते हैं। भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी विभागीय प्रधान सचिव एसएन मिश्रा बैठा हुआ है यह शिवराज की चांडाल चौकड़ी का एक बड़ा शातिर डकैत है। मंत्री तुलसी सिलावट की तरह यह भी भेजो करना है वह करो हमें तो हमारा हिस्सा पहुंचाते रहो। स्वाभाविक है कि जब हिस्सा पहुंचाया जाएगा तो भ्रष्टाचार करना तो आवश्यक है।

Tax Invoice

...E FURNITURE INDUSTRIES
...RI INDUSTRIUAL AREA
... ROAD UJJAIN
...N: 23BQVPS8282C1ZA
State Name : Madhya Pradesh, Code : 23
...: 94250-93008,94250-92224
...: myhome_ujjain@yahoo.com

Invoice No. 18 | Dated 6-Apr-23 | Supplier's Ref. | Other Ref.

000356

E.E.W.R.D
DEWAS
: Madhya Pradesh, Code : 23

Sl No.	Description of Goods	Quantity	Rate	per	Disc. %	Amount
1	ITEM 18% 9403 BED	1 NOS	32,430.00	NOS		32,430.00
2	ITEM 18% 9403 MATTRESS	1 NOS	16,646.00	NOS		16,646.00
3	ITEM 18% 9403 BED SIDE TABLE	1 NOS	5,235.00	NOS		5,235.00
4	ITEM 18% 9403 PILLOW	2 NOS	782.50	NOS		1,565.00
5	ITEM 18% 9403 BED SHEET	1 NOS	2,635.00	NOS		2,635.00
6	ITEM 18% 9403 BLANCKET	1 NOS	2,645.00	NOS		2,645.00
7	ITEM 18% 9403 PVC CHAIR	6 NOS	1,265.00	NOS		7,590.00
8	ITEM 18% 9403 PVC CENTER TABLE	1 NOS	3,450.00	NOS		3,450.00
						72,196.00
	FRIGHT (GST)					1,500.00
	C GST					6,632.65
	S GST					6,632.65
	Less : ROUND OFF					(-)0.30
	Total	14 NOS				₹ 86,961.00

Amount Chargeable (in words) E. & O.E
INR Eighty Six Thousand Nine Hundred Sixty One Only

HSN/SAC	Taxable Value	Central Tax Rate	Central Tax Amount	State Tax Rate	State Tax Amount	Total Tax Amount
9403	73,698.00	9%	6,632.65	9%	6,632.65	13,265.30
Total	73,698.00		6,632.65		6,632.65	13,265.30

Tax Amount (in words) : INR Thirteen Thousand Two Hundred Sixty Five and Thirty paise Only

PAID
Vr. No. 18 Date 28.4.23
Cheque No 523659
Executive Engineer
Company's PAN : BQVPS8282C
Declaration
We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Company's Bank Details
Bank Name : UCO BANK
A/c No. : 08570210001776
Branch & IFS Code : FREEGANJ & UCBA0000857
Executive Engineer, Water Resources Division Dewas (M.P.)
for MYHOME FURNITURE INDUSTRIES
Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

धर्म का विध्वंसकारी सन्त्राप

नए वर्ष में नई उमंगों और खुशियों से भरी नई रोशनियों का भारतवासी कितना भी तड़फ़ते -तरसते करले बड़ी बेसब्री से इन्तज़ार हैं मग़र जीवन के हर लम्हों पर व ज़िंदगी जीने की बुनियादी खुशहाली के हर कतरे - हर मुहाने पर सरकार तो देगी संकट से भरी अतीव त्रासदियों का अभिशप्त अपघात हैं, पुलिस का कुचलता आतंक, सरकारी दमन का अधिनायकवाद और अन्यायी सज़ाओं में फँसाने वाले संगीन क़िस्म के फ़िरंगी अंग्रेज़ीयत की तानाशाही व औरंगज़ेब की घृणित क्रूरता से भी अधिक घातक नादिरशाही वाले लादे नए काले क़ानूनों से सम्पूर्ण प्रजा पर पाशविकता से भरे अत्याचारों से होगा लोकतंत्र व प्रजातांत्रिक अधिकारों पर भीषणतम कुठाराघात हैं, हाड़तोड़ महँगाई, भीषणतम बेरोज़गारी, भयावह भ्रष्टाचार, बेपनाह भूखमरी, अथाह आर्थिक लूट-खसोट का घातक मायाजाल, आर्थिक बर्बादी का भारी मकडजाल, आर्थिक व सरकारी संरक्षण में पनप रहा खौंफ़नाक माफ़ियावाद, देश के खज़ाने लुटाकर लादी जा रही तबाही, हर घर दस्तक दे चूकी कंगाली, राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकट,घोर वित्तीय दिवालियापन और विदेशी क़र्ज़ पर क़र्ज़ लाकर देश की हज़ारों पीढ़ियों को आजन्म कर्जदारी में फँसाकर विनाश का ज़ो विध्वंसक़ारी विस्फोटक सन्त्राप थोपा जा रहा हैं वही देश के जन जन के लिए भयावह भीतरघात हैं.

पूरे देश क़ो गुमराह करते धर्म व अध्यात्म के मूल्यों को बड़ी धुर्तता से अपमानित बना रहे हैं। देश के कई नामी गिरामी व महान सनातनी सन्त देश के चौकीदार पर आरोप लगाते उन पर विश्वपूज्य दैव प्रभुश्री राम क़ो असहाय सा बना अपने झूठे रुतबे के पागलपन में प्रभुश्री को छोटा बता खूद क़ो बड़ा व महान बताते प्रभुश्री पर रहम की धृष्टता से उन्हें अंगुली थामे अधना सा दिखा सनातनी धर्म अध्यात्म क़ो ठेंगा दिखा रहे हैं। जगत संकट के हरणदाता महाबली प्रभु श्री हनुमानज़ी को भी दयनीय समझ उन्हें सिर्फ़ माला पहनाने वाला खिलौना बनाकर उनके महत्मय के साथ जधन्य खिलवाड़ करने वाले भाजपा के ये कुनबे धर्म व अध्यात्म क़ो भी जलील करते शर्मसार बना रहें हैं। एक नही एक साथ दो दो जगदगुरु... श्री शंकराचार्य परमपूज्य श्री निश्चला नंद सरस्वती जी व परमपूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरा नंदज़ी प्रभुश्री राम को हाथ पकड़ मंदिर की ओर ले जाने की धृष्टता और अधूरे मंदिर निर्माण की प्रतिष्ठा क़ो असुरी राक्षसी कार्य बताते इसे अनिष्ट की संज्ञा देते कह रहे हैं कि राजनैतिक स्टंट व बोटों के लिए सारे सनातनी मूल्यों क़ो कुचल नक़ली सन्तों की ताक़त पर पूरे देश क़ो गुमराह करते धर्म व अध्यात्म के मूल्यों को बड़ी धूर्तता से अपमानित बना रहे हैं.

साप्ताहिक समय माया

सहजन के फायदे

सहजन का पेड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल है और यह सूखे का सामना कर सकता है। इस पेड़ के महत्वपूर्ण भाग इसकी फली, फूल और पत्तियाँ हैं, सहजन पारंपरिक औषधियों का एक प्रमुख तत्व है क्योंकि इसकी फली और पत्तियाँ दोनों ही कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए फायदेमंद हैं। सहजन के पत्ते और फली आमतौर पर दक्षिण भारतीय व्यंजनों में पाए जाते हैं। सहजन की फली का उपयोग कई व्यंजनों में किया जा सकता है, जैसे ड्रमस्टिक करी, सांभर और दाल। सहजन की पत्तियाँ कई हजारों वर्षों से अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक औषधियों के रूप में सहजन की पत्तियों के फायदे नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों से भी सिद्ध हो चुके हैं। आइये जानते हैं सहजन की पत्ती के फायदे।

सहजन की पत्ती के फायदे

सहजन पत्ती के फायदे बहुत हैं और इस पौधे का उपयोग सुंदरता से लेकर विभिन्न बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने में मदद करता है। सहजन के पत्ते के फायदे कुछ इस प्रकार हैं:

1. कैंसर से लड़ता है

सहजन के अर्क में ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर के विकास को रोकने में सहायता कर सकते हैं। इसमें 'नियाज़िमिसिन' नामक पदार्थ भी होता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को दबा देता है।

2. बैक्टीरिया से बचाव करता है

चूंकि इसमें एंटीफंगल, रोगाणुरोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, सहजन की पत्तियां उन संक्रमणों से लड़ती हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के कारण होते हैं। ये ई. कोली, राइजोपस और साल्मोनेला हो सकते हैं।

3. घाव भरने में सहायक

सहजन अर्क घाव भरने में सहायता करने और निशान का दिखना कम करने के लिए फायदेमंद है।

4. अस्थमा का इलाज कर सकता है

सहजन अस्थमा के कुछ हमलों की कठोरता को कम करने और ब्रोन्कियल संकुचन से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकता है। साथ ही, यह फेफड़ों के स्वास्थ्य और सांस लेने में मदद करने के लिए सिद्ध हुआ है।

5. उच्च रकत चाप को काम करता है

सहजन में नियाज़िमिनिन और आइसोथियोसाइनेट जैसे यौगिक होते हैं जो धमनियों को मोटा होने और उच्च रक्तचाप पैदा करने से रोकने में मदद करते हैं।

6. आँखों के लिए अच्छा है

सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत सुधारने में फायदेमंद होते हैं। सहजन रेटिनल वाहिकाओं के विस्तार को, केशिका झिल्ली को मोटा होने से और रेटिनल हानि को रोक सकता है।

7. मधुमेह का उपचार कर सकता है

सहजन पेशाब में ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर और प्रोटीन की मात्रा को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों का परीक्षण किया गया है उनमें हीमोग्लोबिन और कुल प्रोटीन की मात्रा में परिणाम के रूप में वृद्धि हुई है।

8. हृदय प्रणाली की रक्षा करें

सहजन अर्क में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय संबंधी क्षति को कम करने में सहायता कर सकते हैं। यह भी दिखाया गया है कि ये एंटीऑक्सिडेंट हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।

9. किडनी की बीमारियों से बचाता है

अगर लोग सहजन के अर्क का सेवन करते हैं, तो उन्हें गुर्दे, मूत्राशय या गर्भाशय की पथरी होने की संभावना कम हो सकती है। सहजन में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सामग्री गुर्दे की क्षति को कम करने में मदद कर सकती है।

10. सिकल सेल रोग और एनीमिया में सहायक

सहजन के उपयोग से एक व्यक्ति का शरीर अधिक आयरन को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता है, जिससे उनकी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है। एनीमिया और सिकल सेल रोग के उपचार और रोकथाम में सहजन के अर्क को बेहद फायदेमंद माना जाता है।

वो थे सहजन की पत्ती से लाभ। आइए अब बात करते हैं सहजन की फली के फायदे।

सहजन फली के फायदे

1. आपके इम्यून सिस्टम को ताकत प्रदान करता है

सहजन की फली में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है। ये रक्त शोधन में मदद करते हैं। सामान्य सर्दी, फ्लू या खांसी होने पर अक्सर लोग सहजन का सूप लेते हैं।

2. स्वस्थ यकृत को बढ़ावा देता है

सहजन की फली कुछ रसायनों के विकास को बढ़ाती है जो हानिकारक विषाक्त पदार्थों से आपके लीवर की रक्षा करते हैं।

3. हड्डियों को मजबूत करे

सहजन की फली और बीजों में कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यह गठिया और कमजोर हड्डियों का प्रबंधन करते हुए वृद्ध वयस्कों में हड्डियों की अच्छी ताकत बनाए रखने में सहायता कर सकता है।

4. त्वचा को स्वस्थ बनाए रखें

सहजन फली विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों में एक घटक के रूप में मौजूद हैं। इनमें हाइड्रेटिंग और क्लींजिंग प्रभाव होते हैं जो त्वचा को अच्छी स्थिति में रखने में मदद करते हैं। यह पर्यावरण में प्रदूषकों से त्वचा की रक्षा भी करता है। आप पिंपल्स और फोड़े-फुंसियों के इलाज के लिए सहजन की फली का पेस्ट बना सकते हैं।

सहजन के फूल के फायदे

सहजन के फूलों के कई शारीरिक और औषधीय लाभ हैं। इसके विस्मयकारी औषधीय लाभों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये उनमे से कुछ है:

1. प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्त्रोत

शाकाहारी लोग सहजन के फूलों के लिए जा सकते हैं यदि वे पौधे-आधारित स्त्रोतों से उच्च मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहते हैं।

2. कैंसर से बचाता है

ड्रमस्टिक के फूलों में नियोमाइसिन की मौजूदगी कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकती है।

3. यौन अक्षमता का इलाज कर सकते हैं

माना जाता है कि सहजन के फूल यौन अक्षमता का इलाज करते हैं और एक एनर्जाइज़र के रूप में कार्य करते हैं।

4. आवश्यक विटामिन से भरपूर

सहजन के फूल विटामिन बी1, बी2, बी3, ए और सी का एक अच्छा स्त्रोत हैं, जो शरीर को पोषण के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं।

हमें उम्मीद है कि सहजन की पत्ती के फायदे के बारे में ऊपर दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। इस अद्भुत पौधे से तैयार किए जा सकने वाले विभिन्न व्यंजनों और पेय के बारे में जानने के लिए और अन्वेषण करें।

हड्डियों को मजबूत ही नहीं डायबिटिज को भी करती है कंट्रोल सहजन की फली

सहजन फली की सब्जी तो अधिकांश लोगों ने खाई है, लेकिन इसके गुणों के बारे में कम ही जानते हैं। यह सब्जी कई बड़ी बीमारियों का इलाज करती है। डॉ. लक्ष्मीदत्ता शुक्ला के अनुसार, सहजन फली को मोरिंगा भी कहा जाता है। यह दुनियाभर में पाया जाना वाले सुपरफूड है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पौधा कहीं भी उग जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वहीं इसकी फलियों में पोषक तत्व, खनिज और विटामिन होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सहजन की फली 300 बीमारियों का इलाज करती है। जानिए सहजन की फली से होने वाले फायदों के बारे में -

सहजन की फली विटामिन सी से भरपूर होती है, जो कई संक्रमणों को दूर रखती है। इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो सामान्य सर्दी, खांसी और फ्लू का प्राकृतिक तरीके से इलाज करते हैं। सहजन की फली का सेवन खासकर सर्दियां में फायदेमंद है।

इसमें ब्लड को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक एजेंट के रूप में काम करती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने वालों को खून की खराबी से होने वाली बीमारियां नहीं होती हैं।

सहजन की फली नियासिन, राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन बी और विटामिन बी-12 का एक बड़ा स्रोत है, जो पाचन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें फाइबर होता है जो पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सहजन की फली के सबसे बड़े फायदों में शामिल है हड्डियों की मजबूती। इसमें प्रचूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है। नियमित सेवन से हड्डियों का क्षरण कम होता है और ताकत बढ़ती है।

सहजन की फली डायबिटिज के मरीजों के लिए भी वरदान है। इसे डायबिटिज के मरीज बिना किसी संकोच के खा सकते हैं। इससे बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से कंट्रोल होता है।

सभी उम्र वालों के लिए फायदेमंद

डॉ. लक्ष्मीदत्ता शुक्ला बताते हैं कि सहजन की फली सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। बच्चे यदि इसका नियमित सेवन करते हैं तो उनका सम्पूर्ण शारीरिक विकास होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम के साथ ही लोहा, मैग्निशियम और फास्फोरस बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके लिए सहजन की फली रामबाण इलाज है। यह शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को जलाने में मदद करती है। इसमें मौजूद फाइबर वजन कम करता है।

इसके नियमित सेवन से त्वचा को जवां रखा जा सकता है। सहजन की फली में मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों के कारण ऐसा होता है। त्वचा को किसी प्रकार का संक्रमण नहीं घेरता है। साथ ही खून साफ होने के कारण फोड़े-फूंसी नहीं होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है जो त्वचा की सुंदरता बढ़ाने का साधन है। यह गठिया, जोड़ों के दर्द और माइग्रेन का इलाज है। सहजन की फली के सबसे बडे फायदों में यह भी शामिल है कि इसके सेवन से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। इसका रस भी कई तरह से उपयोगी है। जैसे रस को कान में डालने से दर्द बंद हो जाता है।

हड्डियों का दर्द खींचकर बाहर कर देती है फली, संतरे से 7 गुना ज्यादा है विटामिन सी, जल्द ही दिखता है असर

मोरिंगा पोषक तत्वों से भरपूर होती है. सहजन की फली खाने से कई बड़ी बीमारियों में बेहद फायदा मिलता है. बदली लाइफस्टाइल के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को ही हुआ है. कम उम्र में ही डायबिटीज, बीपी जैसी बड़ी समस्याएं सामने आने लगी हैं. जोड़ो का दर्द और गठिया जैसी समस्याएं भी अब आम हो गई है. हालांकि हमारी खान-पान की आदतों में बदलाव कर हम खुद को बहुत हद तक हेल्दी और फिट रख सकते हैं. सहजन की फली खाने से न सिर्फ जोड़ो और गठिया के दर्द में आराम मिलता है बल्कि ये सूजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन समेत दिल की स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है.

सहजन सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी पत्तियों में संतरे के मुकाबले 7 गुना तक ज्यादा विटामिन सी होता है. वेबएमडीके मुताबिक इसमें केले के मुकाबले 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है. सहनज में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और अमीनो एसिड भी काफी मात्रा में होता है जो कि बॉडी को हील करने और मसल्स को बनाने में मदद करती है.

1. डायबिटीज – सहजन को डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. कई स्टडी में सामने आ चुका है कि सहजन में इंसुलिन जैसा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है. इसकी पत्तियों में प्लांट कैमिकल पाया गया है जो कि शुगर को शरीर में ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और बॉडी इंसुलिन को कैसे रिलीज करे इसे लेकर प्रभावित करता है.

2. रूमेटाइड अर्थराइटिस – जोड़ों के दर्द और गठिया में सहजन फली और इसकी पत्तियों का सेवन रामबाण साबित हो सकता है. सहजन की पत्तियों का रस स्वैलिंग फ्लूड को कम करता है और इससे रेडनेस और दर्द से भी राहत मिलती है.

3. हार्ट हेल्थ – दिल संबंधी बीमारियों से बचाव करने में सहजन की फली मदद करती है. इसमे मौजूद पोषक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को भी घटाते हैं जिससे दिल संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है.

4. मेमोरी – सहजन की फली और इसकी पत्तियों के रस का सेवन याददाश्त को बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है. इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस दूर करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ब्रेन की सूजन को भी दूर कर सकते हैं.

5. इम्यून सिस्टम – आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर है तो आपको तत्काल सहजन की फली का सेवन शुरू कर देना चाहिए. इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं. पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स की ग्रोथ को धीमा करने में भी मोरिंगा मदद करती है.

सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों का ईवीएम हटाओ, देश बचाओ आंदोलन

मेरी आवाज यथार्थ में जनता की आवाज है। जो नेता होने का पाखंड करने वाले घोर स्वार्थी मक्कार नपुंसक, नामर्द, हिजड़े विपक्षी कांग्रेसियों बसपा सपा रालोद आप आदि नहीं उठा पा रहे हैं।

वह कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों ने संवैधानिकता नैतिकता का आधार बनाकर स्वयं अपनी यात्रा प्रारंभ की धन्यवाद के पात्र हैं।

यथार्थ में यह आवाज देश के 50 लाख वकीलों को जो जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं?

स्वयं उठानी चाहिए थी।

वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर

अधिवक्ता अधिनियम 1962 के अंतर्गत यथार्थ में न्यायालयीन पेशेवर अधिकारी हैं। जिनका कार्य जिला अधिवक्ता संघों से लेकर और राज्य की परिषदों और सर्वोच्च अधिवक्ता परिषद में पंजीकृत होने के बाद आमजन को न्याय पाने के लिए न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग करना है।

उनकी जिम्मेदारी है कि वे न्याय की गरिमा को केवल न्यायालय स्तर पर ही नहीं वरन न्यायालयीन, शासकीय प्रक्रिया से लेकर व सड़कों के स्तर पर उतरकर आमजन के स्तर पर भी जाकर उसको संरक्षित सुनिश्चित और पोषित करें।

वर्तमान में आज साइन जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जो आंदोलन किया यह उसका उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें आमजन से लेकर किसानों व्यापारियों उद्योगपतियों शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों मजदूर श्रमिकों सबको सहयोग करना चाहिए ताकि आपका व जनता का

न्याय आपको उचित समय पर उचित तरीके से प्राप्त हो सके।

इस आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं और इस नैतिक और सामाजिक कार्य में सभी वकीलों के साथ हूं।

आवश्यकता पड़ने पर वक्त आने पर मैं ऐसे आंदोलन के लिए जो ईवीएम के विरुद्ध उठेगा सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध हूं।

यह हम सब आमजन को प्रतिज्ञा करनी चाहिए और ऐसे आंदोलन में के लिए सड़कों पर उतरकर अपनी सांस रहने तक आने वाली पीढियां के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन में सक्रिय सहयोग करेंगे।

क्या मतलब है इस न्याय यात्रा का

केवल जनता को भ्रमित कर उसका समय बर्बाद करना है

जिस ईवीएम ने सत्ताधीशों के इशारे पर जनता के साथ छल कपट किया। आपसे सत्ता छीनी।

उसकी इच्छा का गला घोट उसके साथ अन्याय किया।

उस ईवीएम को हटाने के लिए यात्रा नहीं पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए।

कांग्रेसियों इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। की 10 साल के ठहराव पत्र के अनुसार इस इवीएम से अब सत्ता हथिया लोगे। सत्ता में रहते ही वो चांडाल इतने सारे छल कपट कर कानून बना देंगे। कि आप हाथ मलते रह जाओगे।

और फिर वो तो आपका छल कपट से नामों निशान मिटाने पर तुले हैं। कांग्रेसियों तुमसे ज्यादा अच्छे तो सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं जो अपने दम पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किए हुए आंदोलन कर रहे हैं

और तुम चाहते हो हरामखोरों कि वे ही सब कर ले, दें और तुम पकी पकाई सत्ता हाथ में लेकर हजम कर जाओ।

साप्ताहिक समय माया

सारी संस्थाओं को 2014 के बाद नकारा बना लूट नाकामियों बर्बादी को छुपाने का षड्यंत्र

पेज 1 का शेष

भारत से आगे ये 4 देश

सिर्फ भारत ही क्यों, बेरोजगारी कई देशों के लिए चुनौती बनी हुई है. कुछ देशों में तो बेरोजगारी की दर दहाई अंकों में है. दी वर्ल्ड रैंकिंग नाम के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के अनुसार, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दक्षिण अफ्रीका में है. इस देश में बेरोजगारी की दर फिलहाल 32.7 फीसदी है. स्पेन और तुर्की में भी बेरोजगारी की दर 10-10 फीसदी से ज्यादा है. 8.8 फीसदी की बेरोजगारी की दर के साथ ब्राजील चौथे स्थान पर है, जबकि इटली 7.8 फीसदी की दर के साथ भारत के बराबर पांचवें पायदान पर है.

सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले देश

दुनिया के करीब एक दर्जन देशों में अभी 5 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी है. भारत के बाद 7.2 फीसदी की बेरोजगारी के साथ फ्रांस का नंबर है. वहीं अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, चीन और कनाडा में भी बेरोजगारी दर 5-5 फीसदी से ज्यादा है. यहां देखें दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले देशों के नाम...

भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है?

जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात आती है, तो भारत दिसंबर 2023 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) $ 2,673 और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) $ 9,180 दर्ज करता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग 2023 के अनुसार, यह भारत को लगभग 129 वें स्थान पर खड़ा करता है। 200 देश. जब विश्व जीडीपी रैंकिंग की बात आती है, तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है; सरकारी दूषित कार्यप्रणाली

रिपोर्ट के मुताबिक, रैंकिंग में भारत का कुल स्कोर 28.7 रखा गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है, जिससे 2022 में इसकी स्थिति और कम होकर 107 (121 देशों में से) हो गई है। हालांकि, सरकार ने रैंकिंग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह एक त्रुटिपूर्ण उपाय है। 'भूख' की जो भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती।

गुरुवार को जारी जीएचआई 2023 ने 2018-22 के दौरान भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर को दुनिया में सबसे अधिक 18.7 प्रतिशत पर रखा है और कहा है कि यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 प्रतिशत और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1 प्रतिशत है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। स्कोर चार घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित हैं: कैलोरी सेवन के आधार पर अल्पपोषण, ऊंचाई के आधार पर बच्चे (पांच साल से कम उम्र) का बौनापन, वजन के आधार पर बच्चे (पांच साल से कम उम्र) का कमजोर होना, और बाल मृत्यु दर (पांच साल से पहले)। चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर, जीएचआई स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100-बिंदु पैमाने पर की जाती है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है (कोई भूख नहीं) और 100 सबसे खराब है।

भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान (102), बांग्लादेश (81), नेपाल (69वां), और श्रीलंका (60) ने सूचकांक में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है।

सरकार की प्रतिक्रिया

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि जीएचआई 2023 रिपोर्ट 'गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है और दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती है।'

'सूचकांक भूख का एक गलत माप है और गंभीर पद्धतिगत मुद्दों से ग्रस्त है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक, 'अल्पपोषित (पीओयू) जनसंख्या का अनुपात', 3,000 के बहुत छोटे नमूना आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।

मंत्रालय ने कहा कि जैसा कि पोषण ट्रैकर पर देखा गया है, बच्चों में वेस्टिंग का प्रतिशत, महीने-दर-महीने लगातार 7.2 प्रतिशत से नीचे रहा है, जबकि जीएचआई 2023 में चाइल्ड वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए गए 18.7 प्रतिशत के मान की तुलना में। इसमें कहा गया है, इस बात का शायद ही कोई सबूत है कि बाल मृत्यु दर (चार संकेतकों में से एक) भूख का परिणाम है।

चीन प्रेमी मोदी ने मोटे कमीशन पर

देश के किये उद्योग धंधे बर्बाद सीमाओं पर घुसपैठ की पूरी छूट

पेज 1 का शेष

मोदी ने चीन के हित में काम किये, इसलिए चीनी मीडिया तारीफ़ कर रहाः कांग्रेस

नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करने वाले चीन के 'ग्लोबल टाइम्स' अखबार में छपे लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन के सरकारी मीडिया ने उनकी प्रशंसा की है, क्योंकि 'चीन की घुसपैठ के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं हैं' और उन्होंने भारत के इस पड़ोसी देश के हितों का ध्यान रखा है.

द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि 'भारत नैरेटिव' खड़ा करने और विकसित करने में भारत रणनीतिक तौर पर अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय हो गया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की प्रशंसा की गई है.

एक बयान में कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'प्रधानमंत्री के चीयरलीडर्स और उनके लिए ढोल पीटने वाले चीन के आधिकारिक मीडिया द्वारा की गई उनकी प्रशंसा से खुश हैं. और चीन से उन्हें सराहना मिलनी भी क्यों नहीं चाहिए? आखिरकार, यह सिर्फ वही थे, जिन्होंने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से यह बयान देकर कि 'न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनके उस झूठ से न सिर्फ हमारे सैनिकों का घोर अपमान हुआ, बल्कि कोर-कमांडर स्तर की 18 दौर की वार्ता के दौरान बातचीत में हमारी स्थिति भी कमजोर हुई. उनके उस बयान के कारण ही मई 2020 से 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन को कब्जा व नियंत्रण करने में मदद मिली है.'

जयराम रमेश ने बताया कि प्रधानमंत्री के बयान के विपरीत लेह के पुलिस अधीक्षक ने एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि भारत अब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स (निगरानी गस्त बिंदु) में से 26 तक नहीं जा सकता है. ये वे पॉइंट हैं, जहां तक हमारे जवान साल 2020 से पहले तक बिना किसी रोक-टोक के पेट्रोलिंग किया करते थे. आज देपसांग और डेमचोक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र भारतीय सैनिकों की पहुंच से दूर हैं.

उन्होंने कहा, 'जहां पीछे हटने को लेकर वार्ता हुई है – जैसे कि गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स – वहां भारत ने आक्रमणकारियों के लाभ के लिए बफर जोन की मंजूरी दे दी है. वह स्थान जहां परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक बना हुआ था, अब वहां भारतीयों को जाने से रोका गया है. (इसलिए) इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चीनी मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं.'

जयराम रमेश ने भारत-चीन संबंधों में दी गईं विभिन्न रियायतों को सूचीबद्ध किया.

उन्होंने कहा, 'भारत को रूस में उन्हीं चीनी सैनिकों के साथ संयुक्त अभ्यास करने की अनुमति दी गई, जो लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं. 1-7 दिसंबर को 7/8 गोरखा राइफल्स के भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी ने रूस के वोस्तोक-2022 अभ्यास में भाग लिया, जिसमें चीन भी शामिल था. क्या हमारे 20 बहादुर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान इतनी आसानी से भुला दिया गया?'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास भी चीन को अपना प्रभाव जमाने की अनुमति दी है.

उन्होंने कहा, 'मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु का मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए भारत से अनुरोध करना भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है. 2017 में 'जीत' के दावों के बावजूद भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कोरिडोर के पास डोकलाम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीनी सेना का निर्माण कार्य जारी है.'

जयराम रमेश ने कहा कि भारत की लगातार चिंताओं के बावजूद भूटान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि चीन ने भूटान में 'कोई घुसपैठ नहीं की है'.

बयान में उन्होंने आगे कहा, 'और श्रीलंका – जहां प्रधानमंत्री का ज्यादा ध्यान अपने मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने पर है – में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह पर 99 साल की लीज के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. चीन के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले जहाज समय-समय पर बंदरगाह पर रुकते हैं. चीन के संतुष्ट होने के ये सभी कारण हैं.'

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के वादों के बावजूद चीन से तेजी से आयात की सुविधा प्रदान की गई, जिसके कारण देश को 2022 और 2023 में रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ है.

उन्होंने आरोप लगाया, 'चीन की घुसपैठ के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सेना के साथ सहयोग किया, उसे भारत के पड़ोसी देशों में प्रभाव जमाने दिया. साथ ही चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता बढ़ा दी और आरएसएस को उसके राजनयिकों को सम्मानित करने की इजाजत दी. आरएसएस ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में अपने नागपुर मुख्यालय में चीनी राजनयिकों के एक समूह की मेजबानी की थी.'

चीन के राजनयिकों द्वारा आरएसएस के परिसर का दौरा

दिसंबर 2023 में चीन के राजनयिकों के एक दल ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक परिसर का दौरा किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि चीन के राजनयिकों का समूह दिसंबर के पहले सप्ताह में रेशिमबाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया था. शहर में आरएसएस मुख्यालय के अलावा संघ के पास रेशिमबाग में इसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक भी है, जहां स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां होती हैं. अख़बार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि दिल्ली के साथ-साथ मुंबई स्थित देश के वाणिज्य दूतावास से चीनी राजनयिकों की एक टीम वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दौरे पर थी, जहां से वे नागपुर पहुंचे थे. बताया गया है कि सरसंघचालक मोहन भागवत उस समय वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए राजनयिक उनसे नहीं मिल सके. अख़बार के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी भी स्तर के चीनी राजनयिक आरएसएस परिसर पहुंचे थे. इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं. पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इससे संबंधित ख़बर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि चीन के राजनायिक वहां क्यों गए थे, वहां क्या चर्चा हुई और क्या समझौते हुए. उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा कि 'एक तरफ़ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं. दूसरी तरफ़, खबरों के अनुसार चीन के डिप्लोमैट्स संघ मुख्यालय गए. क्यों गए? किसलिए गए? क्या बातचीत हुई?'

90% जैविक जांच औचित्यहीन पैसा वसूली के लिए

पेज 8 का शेष

उसने ढाई सौ करोड रुपए से ज्यादा का भुगतान इन फर्जी चाचू के ठेकेदारों को करके मोदक मिशन कमाया है तो देश में वह बात कैसे झूठा सिद्ध हो सकती है। इसको पाठक जनता को सरकार स्वयं समझे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के सबसे साफ शहर में लोगों की सेहत का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन, आईएम व रेडक्रास के सहयोग से दो लाख से ज्यादा लोगों की 10 तरह की करीब 20 लाख जांचें इंदौर में करवाई। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। करीब 49 से 50 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी एक या दो या इससे अधिक जांच रिपोर्ट सामान्य नहीं आई हैं। कोई ना कोई पैरामीटर गड़बड़ाया है। किसी में शुगर तो किसी में प्रोटीन की कमी मिली। रविवार को इंदौर आ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया यह रिपोर्ट जारी करेंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन बीमारियों का समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो करोड़ों रु. बचेंगे।

इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। दो साल पहले सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों के बाद यह सर्वे शुरू किया गया था। कोविड के बाद युवाओं में भी कई तरह की बीमारियां देखी गईं, जो इसके पहले कम उम्र में नहीं देखी जाती थी। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल लैब की डॉ. विनिता कोठारी से बात की। इसके बाद जिला प्रशासन से चर्चा की गई। कई संस्थाओं की मदद से दो साल पहले यह सर्वे शुरू किया गया था। दो हजार से ज्यादा जगह शिविर आयोजित किए गए। दो लाख लोगों की 10 पैरामीटर के तहत जांचें की गईं। 'हेल्थ ऑफ इंदौर' नाम यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे है।

पहले 1 लाख, फिर 2 लाख की जांच की

2 साल तक चले इस सर्वे के मुताबिक इंदौर की लगभग आधी आबादी ही किसी ना किसी गंभीर लाइफ स्टाइल जनित बीमारियों का शिकार हो सकती है। जब एक लाख लोगों की सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जब 48 फीसदी लोगों की कोई ना कोई रिपोर्ट असामान्य थी। इस बार भी जब संख्या दोगुना हुई है तब भी सर्वे में शामिल करीब 49 से 50 फीसदी लोगों की जांच रिपोर्ट असामान्य मिली है।

सभी आयु वर्ग के लोगों को किया शामिल

सर्वे में सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण में करीब 11% लोगों में ब्लड ग्लूकोज सामान्य से ज्यादा थी। यानी इसे प्री डायबिटीज स्टेज कह सकते हैं। वहीं 20% लोगों में कॉलेस्ट्राल की मात्रा असामान्य थी। इसी तरह करीब 7% लोगों का एसजीपीटी सामान्य से अधिक था। यानी यह वे लोग हैं जिनमें लिवर की बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक है। 6% आबादी में ग्लूकोज व कॉलेस्ट्राल दोनों ही बढ़े हुए थे।

स्वास्थ्य मंत्री टेस्टिंग लैब की शुरुआत करेंगे

दवाओं की टेस्टिंग करने के लिए मप्र की पहली और देश की आठवीं ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन रविवार को इंदौर में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया लैब का उद्घाटन करेंगे। जीपीओ चौराहे स्थित सीडीएससीओ कार्यालय पर बनी लैब का शुभारंभ दोपहर 3.45 मंत्री लैब का शुभारंभ करेंगे। लैब शुरू होने से प्रदेश की 200 से अधिक दवा कंपनियों को अपने सैंपल बाहर नहीं भेजना पड़ेंगे।

जानवरों का आयातित गेहूं मिलेगा देश की सौ करोड़ जनता को

पेज 8 का शेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'दुनिया को खिलाने' का वादा किया। पीएम के वादे के बाद रिपोर्ट आई कि भारत जल्द ही गेहूं के आयात का फैसला ले सकता है। हालांकि, सरकार ने आयात की अटकलों या किसी भी फैसले का खंडन किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि मई में गेहूं का निर्यात बंद करने का फैसला लेने के बाद चार महीने से भी कम समय में सरकार ने गेहूं आयात का फैसला लिया है। हालांकि, एएनआई की रिपोर्ट में सरकार ने आयात की अटकलों का खंडन किया है।

भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद, भारत की पहचान कभी भी एक प्रमुख गेहूं निर्यातक की नहीं रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कहा था कि भारत 'दुनिया को खिलाने' के लिए तैयार है। हालांकि, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चार महीने से भी कम समय के बाद, सरकार अनाज के आयात पर विचार करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि, सरकार ने खंडन कर कहा कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है।

सरकार का जवाब

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रविवार को आई मीडिया रिपोर्ट के बाद स्पष्ट किया कि भारत में गेहूं आयात शुरू होने की संभावना नहीं है। विभाग ने ट्विटर पर 'गेहूं आयात वाली खबर' का जवाब देते हुए कहा, 'भारत में गेहूं आयात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और एफसीआई के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है।'

गेहूं की कीमतें

यूक्रेन और रूस दुनिया के दो प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता हैं। भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर में गेहूं की कीमतें 2,000-2,100 रुपये के मुकाबले 2,400-2,500 रुपये प्रति 100 किलोग्राम तक पहुंच गईं। अगस्त में गेहूं की कीमतें आमतौर पर निचले स्तर पर रहती हैं क्योंकि रबी की ताजा फसलें मंडियों में आती हैं। भारत में वर्तमान समय में गेहूं की कीमत केंद्र के सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल से काफी ऊपर है।

गेहूं निर्यात पर बैन के अलावा...

सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यह कदम देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया था। केंद्र ने गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे मैदा, सूजी (रवा / सिरगी), साबुत आटा और परिणामी आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

संसद में सरकार का बयान

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी सरकार ने आश्वस्त किया था कि केंद्रीय पूल में गेहूं के भंडार की कोई कमी नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, 01 जुलाई, 2022 तक, 275.80 लाख मीट्रिक टन का बफर का मानदंड है। उन्होंने कहा, वास्तविक स्टॉक 285.10 लाख मीट्रिक टन

(एलएमटी) है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि किसानों से निजी खरीद बढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर में सीधे किसानों से अधिक गेहूं खरीदा जा रहा है।

MSP से अधिक कीमत पर बिक रहा गेहूं

केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में बताया, व्यापारियों द्वारा गेहूं की अधिक खरीद के कारण सरकार गेहूं की कम खरीद कर रही है क्योंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति के कारण गेहूं का बाजार मूल्य बढ़ गया था। इसके अलावा, अगर किसान को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, एमएसपी से ऊपर गेहूं की कीमतों का मतलब ये है कि केंद्र को मूल्य गारंटी योजना के तहत कम मात्रा में अनाज खरीदना पड़ा, क्योंकि किसानों को पहले से ही निजी खरीदारों से उनकी उपज की अधिक कीमत मिल रही है।

भारतीयों की जेब पर बढ़ा बोझ

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने feed the world वाली प्रतिज्ञा मार्च में ली थी। रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव के कारण भारत में गेहूं का उत्पादन घटने का खतरा था। उत्पादन में कटौती के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ी। कीमतों में उछाल के कारण नान और चपाती जैसी चीजों का उपभोग करने वाले करोड़ों भारतीयों की जेब पर बोझ पड़ने लगा।

गेहूं आयात पर वित्त मंत्रालय खामोश

बढ़ती किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण अब सरकार विदेशों से खरीदारी करने की तैयारी कर रही है। सरकारी अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में आटा मिलर्स को अनाज आयात करने में मदद करने के लिए गेहूं पर 40% आयात कर में कटौती या समाप्त करना है, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, बातचीत के रूप में पहचाने जाने के लिए निजी नहीं हैं। यह सबसे पहले रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया, वित्त मंत्रालय ने गेहूं के आयात पर जवाब नहीं दिया। खाद्य और वाणिज्य मंत्रालयों के एक प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गेहूं भंडार 14 साल में महीने के सबसे निचले स्तर पर

भीषण गर्मी के कारण बंपर गेहूं की पैदावार न होने के कारण सरकार ने मई में निर्यात प्रतिबंधित कर दिया था। एनडीटीवी डॉटकॉम पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, अगस्त में भारत का गेहूं भंडार 14 साल में महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारत में उपभोक्ता गेहूं मुद्रास्फीति 12% के करीब है।

घरेलू गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाने पर विचार

रिपोर्ट में नोमुरा होल्डिंग्स इंक के अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने कहा, 'वैश्विक गेहूं की कीमतों से युद्ध के जोखिम वाले प्रीमियम को देखते हुए, भारत अधिक आयात के माध्यम से अपनी घरेलू गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाने पर विचार कर सकता है।' हालांकि, घरेलू थोक गेहूं की कीमतें वैश्विक कीमतों से कम हैं, आयात शुल्क में कमी भी इसे एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए आवश्यक होगी।'

अमेरिका में गेहूं का मूल्य

मार्च की शुरुआत में शिकागो में गेहूं 14 डॉलर प्रति बुशल के करीब पहुंच गया। महंगाई का कारण रूस यूक्रेन युद्ध को माना गया। युद्ध के कारण वैश्विक निर्यात खतरे में पड़ गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद, भारत कभी भी एक प्रमुख निर्यातक नहीं रहा है। हालांकि, भारत में कभी ज्यादा आयात भी नहीं हुआ। देश काफी हद तक आत्मनिर्भर था।

गेहूं उत्पादन का अनुमान और हकीकत

अधिकारियों को उम्मीद है कि 2021-22 की फसल लगभग 107 मिलियन टन होगी। हालांकि, फरवरी में 111 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया था। व्यापारियों और आटा मिलों ने 98 मिलियन से 102 मिलियन टन का अनुमान लगाया है। ऐसे में 107 को आशावादी नंबर माना जा रहा है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, देश के सबसे बड़े खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के स्तर से आधे से भी कम रहने की उम्मीद है। इसने अधिकारियों को कुछ राज्यों में अधिक चावल वितरित करने और गेहूं के आटे और अन्य उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया।

धान की कम बुवाई भी चिंताजनक

गेहूं भारत की सबसे बड़ी सर्दियों की फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर और नवंबर में होती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। भारत में चावल उत्पादन को लेकर भी चिंताएं हैं, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए अगली चुनौती हो सकती है। एनडीटीवी डॉटकॉम की रिपोर्ट में मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक के एक अर्थशास्त्री समीर नारंग ने कहा, 'धान की कम बुवाई के कारण अनाज की मुद्रास्फीति चिंता का विषय है।'

साप्ताहिक समय माया

90% पैथो प्रयोगशालाओं में उचित स्टाफ व साधन नहीं

एलोपैथिक चिकित्सा 90% षड्यंत्रकारियों कसाइयों के अड्डे, आइएमए, आईसीएमआर विश्व घातक संगठन की कठपुतली एजेंट

भास्कर में जो समाचार छापा गया संडे बिग स्टोरी के नाम से, उसमें कहा गया शहर के 2 लाख लोगों की 20 लाख जांच 50% की रिपोर्ट सामान्य नहीं। पूरी तरीके से बकवास और झूठी रिपोर्ट थी सच तो यह भी है की 90% पैथोलॉजिकल जांच प्रयोगशालाओं में एमबीबीएस पैथोलॉजी एमएससी पैथोलॉजी या एमएससी जीव विज्ञान के साथ सारा जांच करने वाला सारा स्टाफ एमएससी बीएससी पैथोलॉजी या जीव विज्ञान से पास होना चाहिए। जोकि 90% प्रयोगशाला में नहीं है क्योंकि इतने भारी डिग्री वाले लोगों को 25 से रु. 100000 माह का वेतन देना पड़ता है। अधिकांश जैविक जांच प्रयोगशालाओ में मालिक प्रबंधक जरूर आवश्यक योग्यता एवं डिग्री धारी हो सकता है। परंतु जो नीचे काम करने वाला प्रयोगशाला में रक्त मल मूत्र वीर्य व किडनी लीवर हृदय हृदय के इसीजी एक्स-रे व अन्य प्रकार की सभी जांच करने वाला स्टाफ अधिकांश 10वीं 12वीं पास या कम शिक्षित लोगों को काम चलाऊ काम करने बताए या जिस डॉक्टर ने जांच करने के लिए बीमार को या नमूना भेजा है। की इच्छा अनुसार रिपोर्ट को ऊंचा नीचा करने जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है, के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती है। सच तो यह भी कड़वा है की 90% जांचों की आवश्यकता ही नहीं होती आसानी से डॉक्टर जो अनुभवी भी है वह मरीज का चेहरा हाव भाव, चाल ढाल, शरीर की भाषा से रोग का अनुमान लगा लेते हैं। और यदि नहीं लगा पाते हैं तो वह डॉक्टर भी कृपांक, आरक्षण से, नकल मुन्ना भाई की स्टाइल में परीक्षा पास करके निजी चिकित्सा महाविद्यालय के मोटे दान चंदा देकर डॉक्टर बन गए होते हैं। जिनका हर जांच प्रयोगशाला से 40 से 60-70% तक का कमीशन होता है। इसलिए बीमारियों की 90% जांचों की आवश्यकता ही नहीं होती। पर डॉक्टर अपनी मोटी कमाई के लिए तिल बराबर छोटी सी बीमारी को मरीज को डरा धमकाकर मानसिक दवाब बना बीमारियों को.ताड़ बना बताकर मरीज को लूटा करते हैं।

यह कहानी और कड़वा सच स्वास्थ्य के एलोपैथिक चिकित्सीय क्षेत्र में इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर का हीं नहीं प्रदेश के हर छोटे शहरों में भी यही सब कुछ चल रहा है और यह हालत पूरे देश के निजी व सरकारी संस्थाओं एलोपैथिक चिकित्सीय अस्पतालों, सरकारी व निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से लेकर क्लिनिक नर्सिंग होम्स अस्पतालों की है। बेशक इस सारे खेल के पीछे अमेरिका के विश्व घातक संगठन व वह उसको धन देने वाली अमेरिकी यूरोपियन दवा टीका इंजेक्शन चिकित्सीय उपकरण उत्पादक कंपनियों की मोटी कमाई के षड्यंत्र का हिस्सा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च व अन्य सभी चिकित्सीय संगठन भारत में भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं अब स्वास्थ्य सेवा का नहीं संभ्रांत जालसाजों षड्यंत्रकारियों की लूटेरे, डकैतों का कसाइयों का अड्डा बन चुका है। उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी से लेकर मंत्री संत्री तक उसके कमीशनखोर वसूलीबाज हैं। मीडिया के जाहिल डकैत अपनी मोटी कमाई करने के लिए सच्चाई से दूर उनके इशारे पर नाच कर टीवी चैनल अखबारों में भयाक्रांति करने वाली खबरें व्यापी कोरोना का तांडव छोटे व्यापारियों दुकानों बाजरो मंदिरों फैक्ट्री उद्योगों को कोरोना की आड़ में देश व दुनिया की तालाबंदी कर आर्थिक सामाजिक और नैतिक रूप से नष्ट कर केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया के व्यापार पर पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक कब्जा कर मोटी कमाई करने का खेल है। जो वैसा का वैसा ही सामने आ गया तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जितने भी निजी और सरकारी पैथोलॉजिकल लब है कारण हमेशा गंभीर बनी रहती है तो इन निजी प्रयोगशालाओं में तो सारे छल कपट से जहां केवल मोटी कमाई उद्देश्य है। तो वह कैसे उच्च शिक्षित उच्च वेतन पर स्टाफ के नियोजन के साथ प्रयोगशाला में लगने वाली मशीन उपकरण जांचों में काम आने वाले रसायन आदि की आपूर्ति और संचालन कैसे उचित व निश्चित तरीके से किया जा सकता है तो स्वाभाविक है उनकी जांच रिपोर्ट भी 90% फर्जी होती है और जिसका

चिपका छाप कर उनकी मोटी कमाई करवाने में आंख मिचकर सहयोग करते हैं जैसा कि आपने कोरोना कल में देखा और जैसा कि समय माया के श्री अजमेर ने लिखा था और कहा था कि सारा खेल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है और उनकी मोटी कमाई के लिए यह विश्व घातक संगठन का फर्जी विश्व उनकी अचानक नियमित जांच किसी गोपनी मॉनिटरिंग एजेंसी से करवाना चाहिए जिन प्रयोगशाला में जांच धरने से करवाई जा रही है उनका आंतरिक संचालन रखरखाव व स्टाफ के साथ उनकी कार्य पद्धति और साधन कितने और कैसे हैं? जब सरकारी प्रयोगशालाओं की हालत तो साधनों और स्टाफ के अनुभव कोरोना कल में न केवल जनता ने बल्कि सरकारी डॉक्टर आदि ने भी कर व देख लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लीनिक खोले थे उसमें उसे पर केंद्र के जल मोदी सरकार ने यही आरोप लगाया है कि

(शेष पेज 7 पर)

देश का गेहूं अडानी निर्यात करेगा

जानवरों का आयातित गेहूं मिलेगा देश की सौ करोड़ जनता को

50 लाख मी. टन से ज्यादा अनाज अडानी के सायलों में

समाचार पत्रों में लगातार खबरें आ रही है कि देश में गेहूं की और चावल की पैदावार कम होने के कारण देश की जनता को बांटने के लिए और चावल आयात किए जाएंगे जो वहां के जानवर भी नहीं खाते। अर्थात देश का अच्छा गेहूं चावल दाल दलहन तिलहन से लेकर कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद लगातार देश के अंदर से सेव की कीमत भी रुपए 30 40 से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई क्योंकि कश्मीर के 370 हटाने के बाद सारे बागानों पर अडानी का कब्जा हो गया है से लेकर अदरक लहसुन तक विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। पहले बाकायदा खबर फैलाई जाती है कि चीन से जाने वाला लहसुन आत्यधिक घातक खराब और विषैला है। वही लहसुन 40-50 रुपए किलो बिकता था अब रु.300 किलो से कम नहीं हो रहा वही हालत रखा है वह अदरक भी फसल के मौसम में भी रु. 200 से कम नहीं हो रहा। क्योंकि मोदी के आका अदानी सारा माल सीधा खेतों से खरीद कर विदेश निर्यात कर देते हैं। जहां-जहां पूरे देश में भाजपा की सरकारी थी वहां अदानी ने 2005 से ही अपने सायलो के गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे। जिनकी क्षमता डेढ़ से 2 लाख मीट्रिक टन की है। पूरे देश में लगभग 400 से ज्यादा अदानी के साइलो गोदाम हैं। जिम अनाज पिछले 8-10 सालों से लगातार भरा जा रहा है और उसे अच्छे गेहूं को लगातार निर्यात करके मोटी कमाई की जा रही है बदले में जानबूझकर पूरे देश में गेहूं चावल जैसे अनाजों की कमी पैदा कर उनकी कीमतें बढ़कर फिर जनता को मुफ्त में बांटने के नाम पर आयत के रास्ते खोलने और उसमें भी दो रु. 5 किलो के गेहूं को 10 से 12 रु.15 किलो में खरीद दिखाकर मोटी कमाई का षड्यंत्र किया जा रहा है। अर्थात समझा जा सकता है कि मोदी अपने मित्र अडानी के लिए कौन-कौन से छल कपट कर रहा है यह कहानी का अदृश्य छोटा हिस्सा है। पर खेल लगातार 2014-15 से अनवरत चल रहा है। कोरोना काल में यह खेल बहुत तरीके से खेला गया।

(शेष पेज 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958